Shri D. C. Sharma: ...to embark on this token strike for which at least according to my commonsense there is no justification?

Shri Sachindra Chaudhuri: I have no information.

श्री प्रिय गुप्त : मिनिस्टर साहब ने इन दो तर्कों पर अपने केस को रखा है कि कम्प्यूटराइजेशन होने से एल० आई० सी० में न तो कोई रिट्रेंचमेंट होगा और न कोई लास आफ एमालुमेंटस होगा । रेलवेज में जब सिम्प्लीफिकेशन आफ एकाउंटस हुआ, तो यह कहा गया था कि सरप्लस स्टाफ को एबजार्ब किया जायेगा, उस को रिट्रेंच नहीं किया जायेगा । लेकिन दो साल के बाद हर जोनल रेलवे में पांच सौ से सात सौ तक क्लर्क सरप्लस हो गए और 1 नवम्बर, 1966 को रेलवे मिनिस्ट्री ने फाइनली कह दिया कि जब काम नहीं है, तो सरप्लस लोगों के बारे मे हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है । जब गवर्नमेंट के एक विग अर्थात रेलवे मंत्रालय में यह हालत है कि वादे के खिलाफ कार्यवाही की जाती है, तो क्या यह मंत्रालय भी ऐसा ही करेगा ? दूसरा प्रश्न "रिट्रेंचमेंट" शब्द की परिभाषा का है । श्री जगजीवन राम को ख्याल होगा कि जब वह रेलवे मिनिस्टर थे, तो कोर्ट ने शिडयल्ड कास्टस और शिडयल्ड ट्राइब्ज के बारे मे यह फैसला दिया था। कि एपायंटमेंट का मतलब प्रोमोशन ट हायर पोस्टस नहीं है ।

Mr. Deputy-Speaker What is your question? Come to the question. We are not talking about Scheduled Castes now.

श्री प्रिय गुप्त : क्या इस मामले में रिट्रेंचमेंट का मतलब सिर्फ एपायंटमेंटस ही है, या प्रोमोशन भी है ? मिनिस्टर साहब कहते हैं कि कोई रिट्रेंचमेंट नहीं होगा । क्या हम समझ लें कि रिट्रेंचमेंट न होने का मतलब यह भी है कि एक क्लर्क के सर्विस में दाखिल होने के बाद उस के लिए मौजदा प्रासपेक्टस आफ प्रोमोशन टु हायर स्केल बने रहेंगे ? अगर आटोमेटाइजेशन से एम्पलाईज का हायर स्केल में प्रोमोशन का स्कोप कम हो जाता है, तो क्या मंत्री महोदय इस को भी रिट्रेंचमेंट कहेंगे या नहीं ? सर्विस में कई ग्रेड होते हैं : हायर स्केल, इन्टरमीडिएट ग्रेड, लोअर ग्रेड और लोएस्ट ग्रेड । कभी कभी हायर ग्रेडज में भी आफिशल्ज सरप्लस हो जाते हैं । क्या उन लोगों को लोअर या लोएस्ट में एबजार्ब या आफसेट किया जायेगा और हायर ग्रेडज में भविष्य मे जो वेकेन्सीज होंगी, क्या वे हायर ग्रेडज के सरप्लस स्टाफ से "ईट अप" हो जायेंगी या उन में लोअर ग्रेड के उन लोगों को लिया जायेगा, जिन का प्रोमोशन ड्यू है ?

Shri Sachindra Chaudhuri: I do not understand whether there is any question at all. It is a statement or a speech.

Shri Surendranath Dwivedy: The question is this. The Minister says that there will be no retrenchment. He asks whether that includes that there will be no promotions also or promotions as usual will continue to be made in the LIC?

Shri Sachindra Chaudhuri: There would be no adverse effect on any of the employees.

Mr. Deputy-Speaker: Papers to be laid.

12.49 hrs.

RE: POINT OF ORDER

Shri Madhu Limaye (Monghyr): On a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: Under what rule.

Shri Madhu Limaye: 376. It says:

> "A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the

[Shri Madhu Limaye]

business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker."

अब देखिये :

"Chapter 18, Resolution for removal of Speaker or Deputy-Speaker from office—Rule 202".

Mr. Deputy-Speaker: I have not come to this yet. You can raise it when I come to that resolution.

श्री मधु लिमये : आप जरा सुनिये। आप पायंट आफ आर्डर के बीच में बोलते हैं। अगर मैंने चैप्टर का हैडिंग बनाया है, तो क्या हुआ ? आप इतना क्यों घबराते हैं ? आप मेरा पायंट आफ आर्डर सुन कर अपना फैसला दीजिए। मेरा पायंट आफ आर्डर एरेंजमेंट आफ बिजिनेस के बारे में है। उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आप सुनते नहीं हैं, इसीलिए तो इस प्रकार का प्रस्ताव लाना पड़ता है :

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा, कहिए।

श्री मधु लिमये : कार्य सूची के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। 202 देखें। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के सम्बन्धी जो नियम है वह इस प्रकार है :

"On the appointed day the resolution shall be included in the list of business to be taken up after the questions and before any other business for the day is entered upon".

अब आप देखिए उपाध्यक्ष महोदय, आज कम से कम आप को धीरज और उदारता के साथ काम करना चाहिए। वैसे तो हर दिन करना चाहिए। लेकिन आज चूंकि इस कुर्सी का मामला आ गया है, आप को हमारे साथ जरा धीरज से और उदारता से व्यवहार करना चाहिए। तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह कार्य-सूची ठीक तरह नहीं बनाई गई है। आज सब से पहले यह प्रस्ताव आना चाहिए था। इसलिए मैं आप को इस पर फैसला मांगता हूं।

Shri Khadilkar (Khed): That applies after admission.

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak: Today, the matter has been put on the agenda so that the motion may be made for grant of leave. This "appointed day" or rule 202 applies after leave has been granted, and then the day is appointed.

श्री मधु लिमये : इसीलिए तो कानून मंत्री इन को नहीं बनाना चाहिए था।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, I invite your attention to yesterday's Order Paper. Yesterday it was correctly taken up, just after the Question Hour. I want to know one thing. On the 23rd, in the provisional list of business, which is circulated to us a day in advance, this was the second item on the agenda, just after the Question Hour, and that is in conformity with rule 202 which has been read by my hon. friend Shri Madhu Limaye. Suddenly it has been changed. I would like to get a ruling from you. The hon. Minister of Law has said, by implication, that when the motion is adopted, when all the formalities are completed under rules 200 and 201, then, rule 202 begins to apply, and the day is appointed for discussion. Our submission is that "appointed day" means the day for the discussion. The discussion starts right from the day of admission or disallowance.

Mr. Deputy-Speaker: Under the Directions from the Chair, arrangement of business, the business before the House—

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, निर्देश और नियम में नियम बड़ा है, निर्देश छोटा है।

Mr. Deputy-Speaker: This is in complementary rule No. 2 in the Rules of Business. "Unless the Speaker otherwise directs on any particular occasion.

the relative precedence of the classes of business before the House specified below shall bring the following order" (1) Oath or affirmation; then there is obituary references, etc., etc. The motion for leave to move a resolution for removal of Speaker|Deputy Speaker comes in the list. In the Order Paper distributed two days before, this item can be there according to the precedence prescribed here. It comes in the list. So, there is no point of order.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्वाइंट आफ आर्डर है। आप के कहने के ऊपर यह आ जाता है। इसलिए आता है कि आप 118 संविधान की धारा देखिए। आज कांस्टीट्यूशन के बिना काम नहीं चलेगा है।

Shri Kapur Singh: (Ludhiana): Sir, you have just now said there is no point of order. Have we understood you correctly? Do you take it that you have said that the point of order is overruled?

Mr. Deputy-Speaker: It is overruled.

Shri Kapur Singh: Thank you, Sir.

श्री मधु लिमये : 118 इस प्रकार है :

"Each House of Parliament may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure and the conduct of its business."

अब मेरा यह निवेदन है कि सब से पहले संविधान, उस के बाद संविधान के मातहत जो कानून बनते हैं वह, तीसरे संविधान के अनुसार जो नियम बनते हैं और चौथे निर्देश या अध्यक्षीय निर्णय। यह निर्देश न नियम को काट सकता है न कानून को काट सकता है न संविधान को काट सकता है। जहां कोई नियम है ही नहीं या नियम के अनुसार निर्देश है, निर्देश के ऊपर हम चल सकते हैं। लेकिन जहां साफ नियम है वहां निर्देश का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आप नियम के अनुसार चलिए न कि निर्देश के अनुसार।

Mr. Deputy-Speaker: Even in this, there is no point of order. Article 118(2) of the Constitution says as follows:

"Until rules are made under clause (1), the rules of procedure and standing orders in force immediately before the commencement of this Constitution with respect to the Legislature of the Dominion of India shall have effect in relation to Parliament subject to such modifications and adaptations as may be made therein by the Chairman of the Council of States or the Speaker of the House of the People, as the case may be."

And the Speaker of the House of the People has issued these Directions and they are as good as Rules. There is, therefore, no point of order. Now, Shri Sachindra Chaudhuri.

Shri Kapur Singh: Again, Sir, you have said there is no point of order. Are we to understand that you have overruled the point of order?

Mr. Deputy-Speaker: Certainly.

12.54 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

STATEMENT ON THE SUGGESTIONS FOR ECONOMY MADE BY SHRI HARISH CHANDRA MATHUR

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): I beg to lay on the Table:—A statement on the suggestion for economy made by Shri Harish Chandra Mathur in pursuance of an undertaking given by him on the 10th November, 1966 in reply to a Supplementary on Starred Question No. 211. [*Placed in Library. See* No. LT-7403/66].

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): We would like to ask some clarifications, Sir.